



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड—1
PART I—Section—1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163]
No. 163]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 1, 1997/भाद्र 10, 1919
NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 1, 1997/BHADRA 10, 1919

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना संख्या 38/(पी एन)/1997—2002

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 1997

विषय :—शुल्क मुक्त स्कीम के तहत जारी अग्रिम लाइसेंसों की निर्यात दायित्व अवधि में पुनर्वैधीकरण एवं वृद्धि

फा. सं. 1/7/145/97-98/पी. सी.-2.—सार्वजनिक सूचना सं. 6 (पी एन)/1997—2002, दिनांक 10 अप्रैल, 1997 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें यह व्यवस्था की गई थी कि 1-10-95 को या उसके बाद शुल्क मुक्त स्कीम के अधीन 12 महीनों की मूल निर्यात दायित्व अवधि के साथ जारी किए गए लाइसेंस 18 महीन की बढ़ी हुई निर्यात दायित्व अवधि के लिए पात्र होंगे और 12 महीने की मूल वैधता अवधि 12 महीने की बढ़ी हुई वैधता अवधि के लिए पात्र होगी तथा निर्यात दायित्व अवधि में आगे पुनर्वैधीकरण और वृद्धि प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-I) 1997—2002 के प्रावधानों द्वारा अधिशासित होगी।

2. निर्यात एवं आयात नीति, 1992—97 के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना (अर्थात् 28-2-1995 से पूर्व) के जारी होने से 30 महीने पहले जारी अग्रिम लाइसेंसों के सम्बन्ध में आयात करने और/या निर्यात दायित्व अवधि में वृद्धि करने के लिए, पुनर्वैधीकरण अनुमत करने के लिए, अन्तर्वर्ती व्यवस्था करने के लिए विभिन्न संस्थाओं और निर्यातकों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। मामले पर पुनर्विचार करने के बाद, महानिदेशक विदेश व्यापार निर्यात और आयात नीति, 1997—2002 के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 28-2-95 से पूर्व जारी किए गए अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में निम्नलिखित व्यवस्थाएं करते हैं:—

- (1) उन मामलों में जहां इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख तक 100% निर्यात पूरा कर लिया गया हो तथा तो कोई आयात न किया गया हो या आंशिक आयात किया गया हो, ऐसे अग्रिम लाइसेंस, मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस और मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस का 31-12-97 तक पुनः वैधीकरण किया जा सकता है।
- (2) उन मामलों में जहां इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख तक 100% निर्यात पूरा कर लिया गया हो तथा निर्यात के कुछ हिस्से को निर्यात दायित्व अवधि की वैधता अवधि के बाद पूरा किया गया हो, निर्यात दायित्व की अवधि के विस्तार को नियमन प्रयोजनों के लिए इस सार्वजनिक सूचना के जारी होने की तारीख तक मंजूरी दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, नियमन, अनुमोदित निर्यात दायित्व अवधि के बाद किए जाने वाले निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के उस भाग पर 5% के बराबर राशि की जुर्माने की अदायगी की शर्त के अधीन किया जा सकता है।

- (3) जहाँ इस सार्वजनिक सूचना की तारीख तक कोई निर्यात और आयात नहीं किया गया है, वहाँ निर्यात दायित्व की अवधि/लाइसेंस की वैधता अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (4) मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जहाँ निर्यात दायित्व पूरा नहीं किया गया है, वहाँ 31-12-1997 तक अन्तिम वृद्धि की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में यह वृद्धि निर्यात दायित्व के पूरा न किए गए मूल्य पर 5 प्रतिशत जुर्माने के बराबर राशि के भुगतान के अधीन होगी।
- (5) मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों के संबंध में जहाँ लगाए गए निर्यात दायित्व का कम-से-कम 50 प्रतिशत तक निर्यात दायित्व पूरा किया गया है, वहाँ 31-12-1997 तक अन्तिम वृद्धि की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में, यह वृद्धि निर्यात दायित्व के पूरा न किए गए मूल्य पर 5 प्रतिशत जुर्माने के बराबर राशि के भुगतान के अधीन होगी।
- (6) जिन मामलों में लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरणीयता का पृष्ठोक्त किया गया है वहाँ लाइसेंसों के संबंध में वैधता अवधि में किसी वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (7) जहाँ क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी की जानकारी में गलतब्यानी/धोखाधड़ी के मामले आये हैं वहाँ लाइसेंसों की निर्यात दायित्व की अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस सार्वजनिक सूचना जारी होने की तारीख के 30 दिन के भीतर ऐसे मामले पूर्ण तथ्यों सहित उचित कार्रवाई के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग समिति को भेजे जाएंगे।
- (8) ऐसे लाइसेंसों के संबंध में ऊपर बताए गए को छोड़कर निर्यात दायित्व अवधि अथवा वैधता अवधि के पुनः वैधीकरण अथवा दोनों में आगे विस्तार के लिए किसी भी हालत में विचार नहीं किया जाएगा।

3. ऐसे लाइसेंसों के अन्तर्गत निर्यात दायित्व अवधि में पुनः वैधीकरण/विस्तार अथवा दोनों लाइसेंस जारी करने वाले क्षेत्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा मूल लाइसेंस और एग्जिम नीति/प्रक्रिया में निर्धारित दस्तावेजों सहित डी ई ई सी जमा करवाने पर सीधे स्वीकृत किए जाएंगे।

4. इसे लोकहित में जारी किया जा रहा है।

एस. बी. मन्नाप्राप्त, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 38(PN)/1997—2002

New Delhi, the 1st September, 1997

Subject : Revalidation and Extension in Export Obligation Period of Advance Licences issued under Duty Exemption Scheme.

F. No. 1/7/145/97-98/PC-IL—Attention is invited to Public Notice No. 6 (PN)/1997—2002 dated 10th April, 1997 wherein it has been provided that the licences issued on or after 1-10-95 under Duty Exemption scheme with original export obligation period of 12 months shall have the extended export obligation period of 18 months and original validity of 12 months shall have the extended validity of 12 months and further revalidation and extension in export obligation period shall be governed by the Provisions of Handbook of Procedures (Vol. 1) 1997—2002.

2. Representations have been received from various Associations and exporters for evolving a transitional arrangement for allowing revalidation for making imports and/or extension in the export obligation period in respect of advance licences issued 30 months prior to issuance of this Public Notice (i.e. prior to 28-2-1995) as per Exim Policy 1992—97. After reconsideration of the matter, the Director General of Foreign Trade by exercising the powers conferred upon him under Paragraph 4.11 of Export and Import Policy 1997—2002 makes the following arrangements in respect of advance licences issued prior to 28-2-95.

- (i) Wherever 100% exports have been completed upto the date of issuance of this Public Notice and no import has been effected or part import has been effected, revalidation of such advance licence (Quantity Based Advance Licence and Value Based Advance Licence) may be granted upto 31-12-1997.
- (ii) Wherever 100% exports have been completed till the date of issue of this Public Notice and part of exports have been effected outside the validity of export obligation period, extension in export obligation period may be allowed upto the date of issuance of this Public Notice for regularisation purposes. In such cases, regularisation may be subject to payment of an amount equivalent to a penalty of 5% on that part of the FOB value of exports which falls outside the approved export obligation period.
- (iii) Where on export and import has been made, till the date of this Public Notice, no extension in export obligation period/revalidation of licence will be allowed.
- (iv) In respect of Quantity Based Advance Licences where export obligation has not been completed, last extension upto 31-12-1997 will be allowed. In such cases, the extension will be subject to payment of an amount equivalent to a penalty of 5% on the unfulfilled value of export obligation.

- (v) In respect of Value Based Advance Licences where export obligation has been completed to an extent of a minimum of 50% of the export obligation imposed, last extension upto 31-12-1997 will be allowed. In such cases, the extension will be subject to payment of an amount equivalent to a penalty of 5% on the unfulfilled value of export obligation.
- (vi) No revalidation will be allowed in respect of licences where endorsement of transferability has been effected by the licensing authority.
- (vii) No revalidation/extension in export obligation period will be allowed in the Licences where misrepresentation/fraud has come to the notice of Regional Licensing Authority. Such cases, with full facts, will be referred to Advance Licensing Committee for appropriate action within 30 days of the date of issue of this Public Notice.
- (viii) No further extension, except as stated above, in the export obligation period of revalidation of the validity period of both on such licences shall be considered under any circumstances.

3. The revalidation/extension in export obligation period or both under such licences shall be allowed directly by the Regional Licensing Authority concerned who had issued the licences upon submission of original licences and DEECs alongwith documents prescribed in the Exim Policy/Procedures.

4. This issues in Public interest.

S. B. MOHAPATRA, Director General of Foreign Trade

